

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

२८. { श्री विहासन सिंह :
श्री महादेव प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६-५७ और १९५७-५८ में जनवरी १९५८ तक कितने मामलों में केन्द्रीय सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग चलाये;

(ख) अधिनियम की धारा ६ के अन्तर्गत अभियोग चलाने के लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने मामलों में स्वीकृति दी गई; और

(ग) स्वीकृति प्राप्त मामलों में से कितने मामले उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर खारिज कर दिये गये कि अभियोग चलाने के लिये दी गई स्वीकृति ठीक शब्दों में नहीं दी गई थी अर्थात् स्वीकृति का आदेश उचित ढंग से दिया गया नहीं माना गया और इस कारण अपराधी निर्दोष छोड़ दिये गये ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :
मांगी गई सूचना नीचे दी गई है :—

१९५६-५७	१९५७-५८
५७	५८

* (क) भ्रष्टाचार निवारण ऐक्ट १९४७ के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमों की संख्या . ६५ १००

* (ख) उन मामलों की संख्या जिनमें मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई . ६६ ६०
उन मामलों की संख्या जिनमें मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई ६२ ८५

(ग) कोई नहीं ।

* १९५५-५६ के कुछ मामलों के लिये मांगी गई मंजूरी १९५६-५७ में मिली और कुछ अपसरों के मामलों में, जो पहले ही सविस्त से डिसमिस या भ्रग कर दिये गये थे, मंजूरी की जरूरत नहीं थी ।

Botanical Survey

819. Shri Assar: Will the Minister of Education and Scientific Research be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government undertook botanical survey in the Bombay State during 1957; and

(b) if so, in which part and when?

The Deputy Minister of Education and Scientific Research (Dr. M. M. Das): (a) Yes, Sir.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha when collected.

Election Petitions

820. Shri L. Achaw Singh: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of election petitions received by the District Judges in the Union territories of Manipur, Tripura and Himachal Pradesh respectively out of the elections to the Territorial Councils in 1957;

(b) the number of election petitions still pending with the District Judges in each Union territory and the number of petitions disposed of; and

(c) whether any election to the Territorial Councils has been declared void?

The Minister of Home Affairs (Shri G. B. Pant): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.